Vol III Issue VIII Feb 2014

Impact Factor : 2.2052(UIF)

ISSN No :2231-5063

International Multidisciplinary Research Journal

Golden Research Thoughts

Chief Editor
Dr.Tukaram Narayan Shinde

Publisher
Mrs.Laxmi Ashok Yakkaldevi

Associate Editor
Dr.Rajani Dalvi

Honorary
Mr.Ashok Yakkaldevi

IMPACT FACTOR : 2.2052(UIF)

Welcome to GRT

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2231-5063**

Golden Research Thoughts Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Catalina Neculai
University of Coventry, UK

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Horia Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest,Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

.....More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.aygrt.isrj.net

Golden Research Thoughts
ISSN 2231-5063
Impact Factor : 2.2052(UIF)
Volume-3 | Issue-8 | Feb-2014
Available online at www.aygrt.isrj.net

"अनुज्ञा पत्र (लायसेंस) एवं निरिक्षक राजस्व एक समालोचनात्मक अध्ययन"

चन्द्रशेखर पाण्डे
अतिथि विद्वान (वाणिज्य) शासकीय नवीन महाविद्यालय, विदिशा (म.प्र.)

सारांश :-भारत ने सामाजिक प्रजातंत्र की नीतियाँ १९४७ से १९९१ तक अपनाई है एवं उनका अनुवर्तन किया है | अर्थव्यवस्था की गहन नियमन, सुरक्षात्मक सार्वजनिकस्वामीत्व, व्याप्त भ्रष्ट्राचार एवं धीमी प्रगति की विशेषताएं रही है | १९९१ से लगातार उदारीकरण ने अर्थ व्यवस्था को वाजार आधारित प्रणाली में संचालित किया ही | सन २000 में उत्तम आर्थिक नीति ने अर्थव्यवस्था को आर्थिक वृध्दि एवं पुर्न जीवन दर को वढ़ाया है | चालू वर्षो में शहरों में व्यावसायिक विनियमों के संचालन के लिए उदारीकरण को सतत्रूप से अपनाया गया है | विश्व बैंक के अनुसार २0१२ में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीव्रतम वृध्दि वाली अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुई है | परन्तु सन २00१ में भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत का सकल घरेलू उत्पाद के ६.८ प्रतिशत था, जो विश्व में सवसे ऊँची होगी | वर्तमान अध्ययन, भारत की आर्थिक संभाव्य सर्वशक्तिमान वनाने की उस प्रकृति को समझना है जो अर्थव्यवस्था की सामाजिक से उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में गहरे गड्ढे से निकाल कर परिवर्तित कर सके |

प्रस्तावना :

भारत के आर्थिक इतिहास में १९९१ का वर्ष एक प्रतीक चिन्ह छोड़ गया है | १९७0 के वाद आर्थिक उदारीकरण ने आर्थिक सुधारों को २४ जुलाई १९९१ से प्रारंभ किया | भुगतान संतुलन की समस्या एवं संकट ने वड़े सुधार कार्यक्रमों को अपनाने पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के माध्यम से अपनाने पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के माध्यम से अपनाया गया है |

विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के माध्यम से त्वरित विदेशी मुद्रा भंडार को पुरा करने का प्रयास एवं संकट को समाप्त करने का प्रयास किया गया है | देश ने गहरे आर्थिक संकट का सामना किया है, पंरतु यह संकट नीति नियामकों के द्वारा देश में आधारभूत परिवर्तन लाने के रूप में परिवर्तित कर दिया गया | एक कार्य क्रम जिसमें स्थिरीकरण वनाम संगठनात्मक समायोजन साधनों को रखकर समष्टि आर्थिक स्थिरता एवं उच्च आर्थिक वृध्दि दर को पाने का परिदृश्य देखा गया | यह सत्य है कि १९८0 में भी आर्थिक उदारीकरण के कुछ संकेत दिखाई दिये थे | परन्तु वे प्रयास असमन्वयकारी, अन्तरालकारी, असामासिक थे | नई आर्थिक नीति की मुख्य वाधा उत्पादन एवं कार्यक्षमता में सुधार कर प्रणाली में प्रतियोगिता की उपयुक्तता उत्पन्न करना रहा | वे उपलब्धि आर्थिक वृध्दि की वाधाओं को दूर कर प्राप्त की जाना थी | उदारीकरण की प्रक्रिया का तात्पर्य अनुज्ञापत्रों स्वीकृतियों एवं नियंत्रण का अनुरक्षित न करना है |

प्रगति ः

विगत ६३ वर्षो में अनुज्ञापत्रों (लायसेंस) एवं निरिक्षण राज के सुधारों की वृहत उपलब्धि की अर्थव्यवस्था ने एक गतिहीन अर्थव्यवस्था से उदारीकृत अर्थ व्यवस्था में देखा है | देश के प्राचीन नेता युध्द पुर्व अवधि में सोवियत संघ में समाजवाद की सफलता से अत्यन्त प्रभावित थे | १९५0 से १९६0 के दशक में राज्यों ने स्वयं निगमित उपक्रमों को प्रारंभ कर अर्थव्यवस्था की ऊँचाईयों की ओर क्षेत्र की समानांतर समताओं जैसे इस्पात एवं शक्ति, औद्योगिक उत्पादन १९६0 के मध्य तक १९७0 के विनियमों की सहायता से प्राप्त करने का निर्देशन किया गया जो औद्योगिक उत्पादन के अतिरिक्त एक लक्ष्य आधारित विशेषता थी | प्रथम तीन दशक तक औद्योगिक अनुज्ञापत्रों के माध्यम से अत्याधिक विनियमों के रूप में विशेषति किया जा सकता है | एक उद्योग को स्थापित करने के लिये अनुज्ञापत्रों के रूप में स्वीकृतियां पूंजीगत वस्तुओं, कच्चे माल, घटकों एवं पुंजी वृध्दि के लिये आवश्यक थी |

१९८0 के प्रारंभ में आर्थिक नीति पर कुछ पुर्नविचार प्रारंभ हो गया था | जवकि पूर्व की व्युह रचना, जो आपात प्रतिस्थापन, लोक उपक्रम ध्यान हटाने एवं निजी क्षेत्र की कार्यप्रणाली के पहलू को नियंत्रित एक साक्ष्य था | परन्तु नीति का प्रभाव केवल उदारीकरण के पहलू को नियंत्रित करने का था | १९८0 के दशक में आर्थि क उदारीकरण (स्वामीनाथन एवं अय्यर) के लिये देश की अर्न्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास १९८१ मे तेल सेंध के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ऋण लेने के लिये जाना पड़ा | संवेगात्मक उदारीकरण के कारण सकल घरेलू उत्पाद ३.५ से ५.६ प्रतिशत एवं गरीवी का अनुपात स्वंतत्रताके पश्चात्पहली वार गिरा है | संवेगी उदारीकरण ने केवल १९९0 में संवेगों को मोमेन्टयसे प्राप्त किया | २४ जुलाई १९९१ को भारतीय अर्थव्यवस्था का विचलन विन्दु कहा जा सकता है | जव तात्कालीन वित्त मंत्री

मनमोहन सिंह ने केन्द्रीय बजट प्रस्तुत कर देश के इतिहास में परिवर्तन की मुहर लगा दी |

भारत के आर्थिक सुधारों को एक बार में लागू कर बाधाएं दूर कर इतिहास बना दिया | एक वित्त मंत्री के रूप में १९९१ से १९९६ तक मृदुभाषी केम्ब्रिज शिक्षित सिंह ने भारत की प्रतिबंधित अर्थव्यवस्था के स्थान पर स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के रूप में खोल दिया एवं अनुज्ञापत्र (लाईसेंस) राज को समाप्त कर फर्मो के स्वतंत्र प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया |

१९९१ में भारत विदेशी विनियम की दौड से दुर हो गया और सोने (स्वर्ण) को गिरवी रखकर स्थिति को नियंत्रित किया गया | संगठनात्मक परिवर्तन स्पष्टतः आवश्यक थे | १९९१ में सोवियत संघ विघटित हो गया और समाजवाद की अधिकता निरूत्तर हो गई थी | भारतीय राजनेता इसे अस्वीकार न कर सके | और उनके अचानक विचारोत्प्रेरक परिवर्तन हेतु सोच को जन्म दिया | खाली खजाने को भरने का उदारीकरण ही एक उपाय था | इसने अर्धपाश्य (half baked) उदारीकरण को सुधारों के साथ क्रमशः शनै ः शनैः आंशिक तौर पर नेतृत्व किया |

जो सुधार प्रधानमंत्री नरसिंहम्हाराव के नियंत्रणाधीन प्रांरभ किये गये थे, उन्हीं को युनाइयेड फंट गर्वन्मेंट ने आगे बढ़ाया | यद्यपि लेफ्ट पार्टीज ने उदारीकरण की एक सुर में आलोचना की | १९९८ में अटल विहारी वाजपेयी की अध्यक्षता मे राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार सत्ता में आई और सुधार की प्रक्रिया को सतत्‌रखकर उस पर आश्रित हो गई |

राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन सरकार पर एशियाई आर्थिक संकट का सत्ता के प्रारंभिक वर्ष में दबाव बढ़ा | परन्तु भारत ने एन.डी.ए. सरकार की अवधि समाप्ति तक शांत तुफान की तरह अर्थव्यवस्था को चलाया | १९९0 ये विभिन्न सरकारों ने विशेषकर कांग्रेस सरकार ने १९९१ में प्रारंभ किये गये सुधारों का अनुवर्तन एवं सराहना की | १९९६१९९८ के मध्य युनाइटेड फ्रंड सरकार ने इसे जारी रखा | १९९८ में भारतीय जनता पार्टी ने एवं १९९९ मे पुनः राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने किया | बाद में सयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (द्वितीय) ने आज पर्यंत तक इन सुधारों को जारी रखा है | इससे प्रतीत होता है कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली सुधारों के मुल निर्देशन तत्वों के प्रति सदैव जागरूक रही है | उदारीकरण का समग्र निर्देशन आज तक नही है, केवल सत्ताधारी दल को छोड़कर |

आर्थिक सुधार संकेतोकं ः

भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतः बाजार अर्थ व्यवस्था की ओर तेजी से उन्मुख हेा रही है | भारत की विगत २0 वर्षो में विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक वृध्दि की क्रमिक परिवर्तन स्थिति जो नियमों एवं विनियमों में भारत की आर्थिक वृध्दि को दर्शाती है निम्न तालिका से स्पष्ट है |

"आर्थिक सुधारों के मुख्य बिंदु"

क्र.	क्षेत्र	सुधार
१.	कोयला	१00 प्रतिशत विदेशी पूंजी निजी कंपनियों के लिए स्वीकृत जो स्थापना एवं परिचालन शक्ति परियोनाओं का संचालन करती है	१00 प्रतिशत विदेशी पूंजी कोयला
२.	रक्षा	२६ प्रतिशत विदेशी पूंजी की स्वीकृति
३.	वित्तीय सेवाएं	१९९९ में वीमा कंपनियों में २६ प्रतिशत विदेशी पूंजी की अनुमति दी गयी	SARFAEST अधिनियम के तहत वित्तीय संस्थानों को ऋणों के संदर्भ में अधिक वैद्यानिक अधिकार दिये गये	
४.	प्रचार (Mdia)	२६ पुतशत विदेशी पूंजी को समाचार एवं चालू मामले वाले चैनलों में तथा अन्य चैनल में १00 प्रतिशत विदेशी पूंजी की अनुमति दी गई	साथ ही रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता को स्विकृति एवं एफ.एम.वेडों की शुरूआता	
५.	खनन्	निजी क्षेत्र की संपुर्ण शर्त प्रतिशत भागीदारी स्वीकृत की गई	
६.	शक्ति	भारतीय तल लिमि., राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम एवं सतलज जल विद्युत निगम में स्वामित्व की अनुमति	
७.	दूरसंचार	१९९९ में दूरसंचार नीति बनाई गई एवं एक वड़ा परिवर्तन हुआ जिसमें स्थायी अनुज्ञा पत्र को राजस्व अंश व्यवस्था में वदल दिया गया	
८.	विशेष आर्थिक क्षेत्र	माल एवं सेवाओं के संवर्द्धन के लिये २00५ में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया	

इन सुधारों ने देश के हर नागरिक की जीवन शैली को ऊँचा किया है और भारत के आर्थिक सुधारों के इतिहास ने उनके योगदान को बढ़ाया है | आर्थिक सुधार संचार, सड़क, रेलवे, शक्ति, स्वास्थ, शिक्षा आदि क्षेत्रों में हुये है | जिन्हे उपर्युक्त तालिका में दर्शाया गया है |

उपर्युक्त के संदर्भ में कुछ संकेताकों से निम्न संभावित सुधारों की अपेक्षा की जाती है |

१)मूलभूत संरचनाओं का क्रियान्वयन एवं निजी क्षेत्र में वृध्दि तथा बैकिंग क्षेत्र में विदेशी सहभागिता |
२)कोयला ब्लॉको के प्रतियोगी आवंदन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना एवं उत्पादन सहभागिता में वृध्दि करना |
३)उर्वरक एवं तेल तथा गैस क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृध्दि |
४)प्रतिरक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को २६ प्रतिशत से बढ़ाकर ७४ . ३ तक अनुमति | यह कोयले के स्थानीक निर्माण | उत्पादन एवं तकनीकी हस्तांतरण की अनुमति |
५)गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियों को भी अनुमोदित किया जा सकता है यदि वे भारतीय रिजर्व बैंक की निर्धारित योग्यताओं को पूरा करते हों |
६)प्रत्यक्ष कर संहिता के विषय में स्कंधधारकों से चर्चा करना ताकि इस स्थिति में १ अप्रैल २0११ से प्रत्यक्ष कर संहिता को लागू किया जा सकें |
७)माल एवं सेवा कर संरचना का अंतिम स्वरूप प्रदान करने के लिए केंद्र राज्यों के वित्त मंत्रियों की समितियों के लिये अधिकृत है, ताकि १ अप्रैल २0११ से माल एवं सेवा कर को परिचित कराया जाकर लागू किया जा सकें |
८)उस कार्यविधि को स्पष्ट किया गया जिसमें अप्रत्यक्ष विदेशी विनियोग (निवेश) के भारतीय कंपनियों में अंशदान की गणना की जा सकें |
९)कीमत, तकनीकी के भुगतान, स्थानांतरण शुल्क, व्यापारिक चिन्ह, ब्रांड का नाम एवं अधिकार शुल्क (रायल्टी) भुगतान के तरीकों को पुर्णतः उदारीकरण से जोड़ दिया गया |
१0)पूंजी खाते की महत्तम परिवर्तनयिता |
११)पेंशन सुधार |
१२)भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अतिरिक्त बैकिंग अनुज्ञापत्र (लाईसेंस) निजी क्षेत्र के निवेशकों को भी जारी किये जागेंगे |

पथक्रम या तरीके ः

अ)आधारभूत संरचना ये देखेगा कि उसमें निवेश से वृध्दि हो रही है एवं वह आर्थिक वृध्दि का एक संकेतांक होगा |
ब)भारतीय आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया अनुगमनात्मक नहीं है चालू वैश्वीकरण, प्रवृत्ति के संदर्भ में |
क)अवसर का आकार बहुत बड़ा है और कंपनियों को अपने व्यवसाय के आकार प्रकार एवं विद्यमान स्तर में वृध्दि का क्षेत्र हैं |
ड)पद कोषों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकेगा जिसमें लाभ कंपनियों के प्रभावपूर्ण निष्पादन एवं परिणामों एवं आधारभूत संरचना की संभावनाओं पर निर्भर करते है, और आर्थिक सुधारों को जारी रख सकते है |

परिणाम ः

वर्ष २000 का दशक आर्थिक सुधारों को समेकित करने का दशक रहा | ९ प्रतिशत सकल घरेलू उत्पादन की वृध्दि कर एवं अचानक विदेशी सहायता की आवश्यकता अनुभव हुई तो भारतीय अर्थव्यवस्था को संभाव्य सर्वशक्ति संपन्न बनाना चाहते थे | कई सुधार वैधानिक नियमों को लागू करने जैसे आपात कर को घटाकर १0 प्रतिशत तक लाना, लघु उद्योगों के लिए आरक्षण चरणवुध्द रूप से समाप्त करने, बैंक फुटकर ऋण प्रदाय में प्रवेश कर सकते है | बैंक पद प्रवेश गृह निर्माण के लिए सस्ते बैंक ऋणों, उपभोक्ता ऋणों एवं वैयक्तिक आवश्यकताओं को पुरा करने संबंधी नियमों को लागू किया गया | इसके द्वारा संबंधित बाजारों को विस्तार होगा | सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी ने आधारभूत संरचना क्षेत्र में एक बड़ी ऊँची कूद दर्ज की है |

भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की ११ वीं सवसे वडी अर्थव्यवस्था है | जो अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत की सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में क्रय शक्ति समता के संबंध में अनुमादित करती है | २00८ की तुलना में आर्थिक वृध्दि दर ६ . ७ प्रतिशत | विगत तीन वर्षो की तुलना में ९ . १ प्रतिशत से कम रही |

भारत की सकल घरेलू उत्पाद में % प्रतिशत

१९५१ ५२ से १९६० ६१	३ से ९ %
१९६० ६१ से १९७० ७१	३.७ %
१९७० ७१ से १९८० ८१	७ से ६ %
१९९१ ९२ से २००१ ०२	७ %
२००२ ०३ से २००५ ०६	७ %
२००५ ०६	९ %
२००६ ०७	९.७ %
२००७ ०८	९.२ %
२००८ ०९	६.७ %
२००९ १०	७.४ %
२०१० ११	८.४ से ८.५ %
२०११ १२	८.५ से ६.९ %
२०१२ १३	६.९ से ९.३ %

भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक वित्तीय प्रभाव के नियंत्रण में प्रारंभ हुई | वित्तिय वर्ष २००९१० में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारी कमी देखी गयी | इसका कुछ क्षेत्रों में बाढ़ के कारण गिरावट दर्ज की गयी | वैश्विक अर्थव्यवस्था के संकट के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में फसलोत्पादन में भी कमी हुई | केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने २००९१० में ७.२ वृध्दि दर अंतिम त्रैमासिक के ७.७ त्के स्तर पर बढ़ेगी ऐसा अनुमान लगाया |

नवीनतम आंकड़ो के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार ६२.३१ रहा | जनवरी मार्च २०१० में भारतीय अर्थव्यवस्था को पुरानी संभावनाओं के आधार पर ८०६त्वृध्दि दर प्राप्त करने की आशा की गयी | आंकड़ो को देखने से पता चलता है कि केवल चीन की अर्थव्यवस्था २०१०११ में ११.१ % के स्तर पर सर्वा धिक रही | १६ अन्य देशों में इसी अवधि में ०.२% ही वृध्दि की | इसी समय आर्थिक सहायता एवं विकास संगठन ने विकसित देशों के समुह जिनमें यूरोप ६० % से अधिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में अंशदान कर रहा था | ने ०.९% के विरूध्द ०.७% एक त्रैमासिकी में युनाईटेड स्टेटस एवं जापान में क्रमशः ०.८१% और १.३% वृध्दि दर्श की गई | यदि आर्थिक सहायता एवं विकास संगठन (OECD)सही है तो भारतीय विश्व के उन चयनिय देशों एक होगी जिसने सन २०११ की तुलना में तेजी से वृध्दि की है | OECD ने सन २०११ में ८.५% वृध्दि दर्ज की है | चीन की वृध्दि धीमी गति से बढ़ी जो २०१० में ११.१% में १ % अनुमानित की गई थी | सरकार ने अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने का प्रयास किए |

सकल घरेलू उत्पाद वृध्दि दर (विश्व की बडी अर्थव्यवस्थाएं % में)

देश	२००१ १०	२०१० ११	२०११ १२	२०१२ १३
चीन	१०.१ %	११.१ %	९.७ %	७.८ %
भारत	७.४ %	८.३ %	८.५ %	६.६ %`
ब्राजील	०.१ %	६.५ %	५.० %	०.९ %
संयुक्त राष्ट्र	२.४ %	३.२ %	३.२ %	२.२ %
जर्मनी	५.० %	१.२ %	१.८ %	०.७ %
रशिया	७.९ %	५.५ %	५.१ %	३.४ %

जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में धीमी प्रगति हो रही थी | तब भारतीय अर्थव्यवस्था अपने नितांत घरेलू बाजार में वृध्दि के उपाय कर रही थी | संवृध्दि का मुख्य संवाहक विनिर्माण क्षेत्र रहा जिसमें १६.३% संकाल्पनिक विगत त्रैमासिक में १०.८ क्षेत्रवार प्रगति की दर दर्ज की गई | यह वृध्दि २००८०९ में ३.२% की न्युनतम वाली वृध्दि की तुलना में अधिक दर्ज की गयी | इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक वित्तीत गिरावट के बावजूद वृध्दि दर को प्राप्त कर सकी |

आर्थिक सुधार जो १९९१९२ में प्रारंभ किये गये | हमारे देश ने सभी क्षेत्रों में ऊँची वृध्दि दर नये वैश्विक अवसरों एवं उपक्रमों की क्रांतिकारी विचारों एवं अभिनव उद्यम कौशल से प्राप्त किया है | १९९१ से भारतीय आर्थिक वृध्दि एवं संरचनात्मक विशेषण थे जो समष्टि अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय स्थिरता के लिये याद रखे जायेंगे | आर्थिक सुधारों ने भारत की ३.९% की १९५० में वृध्दि की तुलना में ६.६% CAESP वृध्दि पिछले दो दशको में दर्ज की गयी | और विगत ५ वर्षो में

८.६५% CAESP की तुलना में आज भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की वित्तीय सबसे वढी वृध्दि वाली अर्थव्यवस्था है | सकल घरेलू उत्पाद ४६ लाख करोड (CIA) के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था युवा उद्यमी एवं पेशेवर व्यक्तियों के द्वारा तीव्रगामी प्रगति दो दशकों में दर्ज की है | माल एवं सेवाओं की मांग में वृध्दि के कारण आज तेजी से वढी है | उपभोक्ता प्रवृत्तियों एवं तरीकों में भी परिवर्तन ने अन्य से तीव्र जैसा कि आशा की गई की वृध्दि दर्ज की | विना दृष्टिकोण एवं संकेतांकों के मास्तिष्क के विश्वस्तरीय कुछ भी पाना कठिन है | पिछले १९ वर्षो में आर्थिक सुधार नीतियों को इसी अवधारणा से क्रियान्वित किया गया है |

निष्कर्ष, के तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीव्रगामी अर्थव्यवस्था है | कुछ संदेहों को छोड़कर | फिर भी यह वृध्दि पर्याप्त नहीं है | भारत को उस वृध्दि की आवश्यकता है जिसके द्वारा विकास, रोजगार, समानता एवं जीवन के अपरिहार्य अवसर को प्रदान करे | हमें आर्थिक सुधारों के अनुभव से सीखना महत्वपुर्ण है | घाटे की अंतराल को कम करना चाहिये | सुधार १०२० वर्षो पुर्व भारत के द्वारा उच्च वृध्दि क्षेत्र पर लागू किये गये थे | परन्तू अव समय आ गया है कि सुधारों को अधिकतम गति प्रदान कर सकल घरेलू उत्पाद दर आर्थिक गतिविधियों की उच्च सकल जीवनोत्पादन में आर्थिक वृध्दि की जाये | आगामी वडे विकास की आवश्यल्ता नीतिगत सुधारों की है | जिसे अर्थव्यवस्था पर सीमित नही रखा जा सकता है | परन्तू ऐसी अपनाए जाने की आवश्यकता है ताकि श्रम पर आर्थिक सुधारों के कारण पडने वाले दुष्प्रभ्आवों को कम किया जा सकें | इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए पिछडे क्षेत्रों में सामाजिक व आर्थिक आधार संरचना के निर्माण के सार्वजनिक कार्यक्रमों को मजवुत वनाया जाना चाहिए | कृषि एवं निवेश को वढावा देकार इसकी वृध्दि दरों की उन्नत किया जाना चाहिए | इसके साथ ही अन्य कठिन सुधार स्वशासन, विस्तार एवं अधुनिकीकरण आधारभूत संरचना के लिए शिक्षा में सुधार योग्य कार्य, चिकित्सा, स्वास्थ सुरक्षा, सामाजिक विकास के साधन वैधानिक एवं न्यायिक सुधार तीव्रतम आर्थिक वृध्दि के लिये अत्यन्त आवश्यक है | प्रोफेसर जान हैरिस निर्देशक, विकास अध्ययन संस्थान, लन्दन स्कुल ऑफ इकोनॉमिक्स ने १८ जनवरी २००५ को चेन्नई में दिए गए अपने व्याख्यान में यह उल्लेख किया है कि "भारत के पास इतना स्वदेशी वाजार उपलव्ध है जो इसे विकास के लिए समुद्र पार के वाजारों पर निर्भर होने की आवश्यकता नही परन्तू इस क्षमता का लाभ उठाने के लिए लोगों के पास आय होती आवश्यक है |" अतः भारत को रोजगार जनन और वृध्दि के साथ आंतरिक सुरक्षा प्रवंधन में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है |

ः पन्त डॉ . जे . सी . सिंह, एस . के . मिश्रा, जे . पी . अर्थशास्त्र पृष्ठ ६३६४ सन २००८ साहित्य सदरन पब्लिकेशन अस्पताल रोड, आगरा |

१)आचार्य एस एवं मोहन आर (२०१०), इंडियन इकोनामी, पी . पी . २७२८ ऑक्सफोर्ड युनिर्वसिटी प्रेस |
२) वारो एवं सालाआइमार्टिन (२००४) इकोनॉमिक ग्रोथ, पी ९६ पीएच आइ लर्निवा न्यु देहली |
३)विजनिस स्टेण्डर्ड (२०१०) मेन्युफेकच्युरिंग एनेवल्स ७ . ४% ग्रोथ इन २००९१० जून १, पी १३ एवेलेवल एट डब्ल्यु डब्ल्यु डब्ल्यु विजनेस स्टेन्डर्ड कॉम |
४) विजनिस स्टेण्डर्ड (कोलकाता) (२०१०), "वोर्डवेस्ट ग्रोथ" पी जून १ जून १ |
५)सी . आई . ए . (सेन्ट्रल इंटेलीजेंस एजेन्सी), द वर्ल्ड फेक्ट वुक, रेंक आर्डर, सी . डी . पी . परजेजिंग पॉवर एवेलेवल एट
http:/www.cia.gov/publication/wordface book/rank order/2011) |
६)इंटरनेशनल मानेटरी फंड (२०१०) रिपोर्ट इंडिया एवेलेवल एट
http:/www.inmf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/weodata/weoxept.aspx
७)मिन्ट (मुंवई) (२०१० ए) "चायना एवं इंडिया टू ड्राइव वलेवल ग्रोथ", मई २७ पेज १२ एवं १३ |
८)मिन्ट (मुंवई) (२०१० वी) "ओईसीडी राइजेंस फोरकास्ट फार इंडिया चाइना मई २७ पेज ११ |
९)मिश्रा ए . आर . (२०१०) "जी . डी . पी . डॉटा इकानीमी रीकवर्स, वट रिस्क परसिस्ट" मिन्ट जून १ ऐवेलेवल एट . www.livemint.com |
१०)मोहन आर (२००४)"फाइनेन्ससियल सेक्टर रिफार्म एण्ड मानेटरी पालिसी द इंडियन एक्सपीरियन्स" आर . वी . आई . वुलेटिन अक्टूवर पेज ११ एवं ३३ |
११)स्वामीनाथन एस एवं अययर ए (२०१०) "५० एट द स्पीड ऑफ १००" द इकोनामिक टाइम्स (कोलकाता) मई ६ पेज ७|
१२)द इकोनामिस्ट (२००८) ए स्पेशल रिपोर्ट आन इंडिया ः इन एलीफेंट नॉट ए टाइवार दिसम्वर ११ पेज ११ अवेलेविल एट
http:/www.economist.com/specia;reprts displaystory.cfm?story-id=१२७४९७३५ .
१३)द इकोनामिक टाईम्स (कोलकाता) (२०१०) मेन्युफेकच्युरिंग हेल्प्स जी डी पी ग्रोथ ७ . ४ % ग्रोथ इन फाई १० मई ३१ |

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- EBSCO
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Golden Research Thoughts
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.aygrt.isrj.net